

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

સુરત-ગુજરાત, સંસ્કરણ ગુરુવાર, 20 અપ્રૈલ-2023 વર્ષ-6, અંક-85 પૃષ્ઠ-08 મૂલ્ય-01 રૂપયે

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com  www.facebook.com/krantisamay1  www.twitter.com/krantisamay1

**अतीक अहमद के कातिल
अरुण मौर्य की अचानक बदली
लाइफस्टाइल, लॉरेंस बिशनोई
से क्या कनेक्शन**

नई दिल्ली। माफिया अतीक अहमद के हत्यारों में अरुण मौर्य सबसे छोटा है और महज 18 साल का है। उसे लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पता चला है कि एक कमरे के घर में परिवार के साथ रहने वाले अरुण मौर्य को महानी चीजें पसंद थीं। यहां तक कि वह जूते तक 10 हजार रुपये के पहनता था। गरीबी और तंगलाली में बचपन गुजारने वाले अरुण मौर्य, जो अंततः

वाल अरुण माय का अदाज फरवरी 2022 में जेल जाने के बाद से बदल गया था। कहे के साथ पकड़े जाने पर अरुण मौर्य को जेल ही गई थी और जब वह जमानत पर वापस लौटा तो एकदम बदल चुका था। गोलगप्पे बेचने वाले कासांज के दीपक कुमार का बेटा अरुण कुमार अब महंगे कपड़े जूते और हाटलों में खाने-पीने का शौकीन हो गया था। उसके शौकिया मिजाज का अदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वह 10 हजार रुपये तक के जते

रिपोर्ट के अनुसार, आजत के कराबा एक एनसापा
ते — — है जिसमें भी — — वार्ड में — —

नता का कहना है कि शद का अगुवाइ म सरकार का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों के मुद्दों पर फेल हो गई है और न ही राज्य के लोगों के

आधिकार, हाई कोर्ट से

नई दिल्ली। केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी भी अविवाहित बेटी को अपने पिता से उचित विवाह खर्च पाने का अधिकार है। भले ही वह किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हो। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजित कुमार की खड़पीठ ने कहा कि इस अधिकार को किसी भी धर्म की मान्यता की आड़ में खत्म नहीं किया जा सकता है। दो जजों की खंचपीठ ने कहा, -एक अविवाहित बेटी का अपने पिता से विवाह संबंधी उचित खर्च पाने का अधिकार, धार्मिक अड़चनों के आड़े नहीं आ सकता। यह हर अविवाहित बेटी का अधिकार है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। किसी भी धर्म के आधार पर इस तरह के अधिकार में भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता है। खंडपीठ ने एक पिता के खिलाफ दो अविवाहित बेटियों की याचिका पर ये फैसला सुनाया है। याचिका दायर करने वाली दोनों बेटियों ने अपनी शादी के खर्च के लिए 45.92 लाख रुपये की राशि की डिक्री जारी करने और अपने पिता की संपत्ति पर डिक्री की मांग करते हुए एक पारिवारिक अदालत का रुख किया था। बां एंड बेंच की रिपोर्ट में आशावादी रोकने की जिसका उनके गई थीं शादी दावा कहा गया है। इसका बावजूद और आधिकार किया जाना चाहिए। इसाई धर्म के विश्वास के लिए मामले धार्मिक विवाह के लिए आवश्यक है।

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी से राहत, तेज हवाएं और आसमान में बादलों का डेरा

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। मंगलवार को जहां तेज गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली थी वहाँ बुधवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर में मौसम अचानक सुहाना हो गया। सुबह से ही चल रही ठंडी हवाओं की बजह से लोगों को तपिश से काफी राहत मिली है। कई इलाकों में आसमान में बादल भी नजर आए। इससे पहले मौसम विभाग ने अनुमान भी जताया था कि बुधवार से गुरुवार तक दिल्ली के आसमान में बादल छाये रहेंगे। इसके अलावा कुछ जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान भी जताया गया था। दिल्ली-एपसीआर में आज सुबह की शुरुआत तेज हवाओं से हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज और कल आसमान में बादलों का डेरा हो सकता है। अनुमान है कि इससे अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। इसके अलावा कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान

22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघण्टे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम का हाल बतावाली स्कार्फेट के मुताबिक, जम्प-कश्मीर वैकल्पिक ऊपर ठंडे और गर्म बादलों का मिश्रण बना हुआ है। इसकी वजह से उत्तर-पश्चिमी भारत के मैदान इलाकों में आंधी और बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं। अनुमान जताया गया है कि 19 से 21 अप्रैल के बीच दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ आंधी चल सकती है और बारिश का भी अंदेशा है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। इससे पहले राजधानी में मंगलवार को भी तापमान में किसी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिली। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से गुरुवार तक दिल्ली के आसमान में बादल छाये रहेंगे। इसके साथ कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में तीन डिग्री तक की कमी आने से राहत के आसार हैं।

मध्य प्रदेश में भी 50 से पहले

भोपाल। साल के आखिरी में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने बनावों को लेकर कई बड़े बादे कर दिए हैं। इन बादों के अनुसार, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रकार बनने पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने अहिलाओं को रह महीने 15 सौ रुपए भी दिए जाएंगे। इसी के साथ एमपी में किसानों की नर्जमाफी को लेकर भी कांग्रेस ने बादा किया बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत प्रकार ने बादा किया था कि राज्य में 1 अप्रैल में 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा और वहाँ लोगों को सिलेंडर पांच सौ

ट के मुताबिक, दोनों बेटियों ने अपनी अर्जी पिता को उस संपत्ति को अलग करने से किले लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा भी मार्गी, उन्होंने दावा किया था कि उनकी मां और रिवार की वित्तीय मदद से वह संपत्ति खरीदी परिवारिक अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता लिए केवल न्यूनतम आवश्यक खर्चों का रखने की हकदार है। इसके साथ ही कोर्ट ने 7.5 लाख की राशि की कुर्की बेटियों के रक्षा के लिए पर्याप्त होगी। दोनों लड़कियों ने अब बताया कि दोनों उच्च अध्ययन कर रही हैं अपने पिता ने उपरके लिए किसी तरह की मदद नहीं की है। पिता ने हाई कोर्ट में दावा किया कि उनकी बेटियाँ और उनकी मां पेंटाकोस्ट और यह समुदाय गहनों के उपयोग में नहीं करता है। इसलिए, आमतौर पर शादियों सोने के गहनों का खर्च उनकी बेटियों के स्टीक की नहीं बैठता है। इस पर कोर्ट ने बिना भेदभाव के अविवाहित बेटियों को उचित वर्च पाने का हकदार माना।

नई दिल्ली। यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने का काम तेज कर दिया है। जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तीन विधानसभा क्षेत्रों की 11 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 2025 तक यमुना को प्रदूषण मुक्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उसी कड़ी में दिल्ली की सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा। जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जल बोर्ड को आंबेडकर नगर और देवली विधानसभा क्षेत्र की अनाधिकृत कॉलोनियों में 25.5 किलोमीटर

लाइन से जोड़ा जाएगा। राजधानी में डॉकर्स्पॉट खत्म करने के लिए 70 हजार अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत शहर विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को बैठक में दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में एक-एक हजार स्ट्रीट लाइट लगाने की मंजूरी दी है। भारद्वाज ने कहा कि वर्ष 2019 में सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना को घोषणा करते हुए दिल्ली में 2.10 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाने का लक्ष्य रखा था। शहर में 10, 20 व 40 बाट की एलईडी लाइट लगाई जा रही हैं।

हर खर्च पाने का को झटका दिल्ली की ये अवैध कॉलोनियां सीवर लाइन से जुड़ेंगी, एके सरकार का फैसला

महिलाओं पर प्रतिबंध को लेकर तालिबान से नाराज हुआ संयुक्त राष्ट्र, हथ खींचने की दी चेतावनी



काबुल। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान को कड़ा सदेश देते हुए कहा है कि अगर यहां की स्थानीय महिलाओं को संगठन के लिए काम करने की अनुमति नहीं दी गई तो अफगानिस्तान से यूएन अपना हाथ खींच लेगा। यूएन डिवेलपमेंट प्रोग्राम के हेड ने यह बात कही है। जानकारी के मुताबिक यूएन इस बारे में अगले महीने कोई फैसला ले सकता है। यूएनडीपी ऐडिमिनिस्ट्रेटर अचिन स्टेनर ने कहा, यह सही है कि हम जहां भी काम कर रहे हैं वहां की सहयोग की क्षमता की समीक्षा करना जरूरी है लेकिन जहां बात मौलिक सिद्धांतों और मानवाधिकारों की आती है, वहां समझौता नहीं किया जा सकता। यूएन ने तालिबान के रवैये पर गहरी चिंता जताई है। यहां यूएन की महिला स्टाफ को काम करने से रोकने

पर यूएन ने नाराजगी जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, बिना महिला कर्मचारियों के जीवन रक्षक कार्यों में बाधा आएगी लेकिन नांगरहार प्रांत में महिलाओं को तालिबान के लोग काम नहीं करने देते हैं। उनपर प्रतिबंध लगाकर रखा है। यूएन ने कहा, अफगान काबिज सत्ता को यह जानकारी दे दी गई कि बिना महिला कर्मचारियों के यूएन का नहीं कर सकता। बता दें कि अगस्त 2021 में जब से अमेरिका ने अपनी सेना व

अफगानिस्तान से हटा लिया था, यहां तालिबान राज कर रहा है। इसके बाद तालिबान ने यहां की जनता पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। खास तौर पर महिलाओं पर बाहर निकलने, शिक्षा और काम करने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। बता दें कि तालिबान ने दावा किया था कि वह इस बार महिलाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा और उन्हें पढ़ाई व काम करने की छूट देगा। हालांकि सत्ता पर काबिज होने के कुछ दिन बाद ही तालिबान ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। तालिबान ने दफतरों से महिलाओं की छुट्टी कर दी और कोएड स्कूल भी बंद कर दिए। अब महिलाओं के लिए अवसर बहुत सीमित कर दिए गए हैं। कुछ जगहों पर घरों में महिलाओं के लिए क्लास चलाई जाती है जहां परुष नहीं जा सकते हैं।

मध्य प्रदेश में भी 500 रु. में सिलेंडर का वादा, एमपी चुनाव से पहले कांग्रेस के ये 5 बड़े ऐलान



इसी के साथ एमपी में किसानों
की कर्जमाफी को लेकर भी

कांग्रेस ने वादा किया है।

चुनाव से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम का वात किया था। सरकार बनने के बाद वहाँ औल्ड पेंशन स्कीम लागू भी कर दी गई है। अब मध्य प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस ने वादा कर दिया है। कांग्रेस के वादे वे अनुसार, राज्य में सरकार बनने पर यहाँ भी कमचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू

की जाएगी।

कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनने पर किसानों की कर्जमाफी का भी वादा किया है। कांग्रेस के वादे के अनुसार, प्रदेश में सरकार बनने पर राज्य के किसानों का कर्ज माफ कर

महिलाओं को 1500 रुपए
 कांग्रेस ने अपने वादे में महिलाओं को भी शामिल किया है। कांग्रेस के वादे के अनुसार, राज्य में सरकार बनने पर प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। कांग्रेस ने वादा किया है कि हर महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे और इसके लिए कोई शर्त नहीं

मातृहंता ।

यह कृतज्ञता की पराकाशा है! दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके के मानसरोवर गार्डन में लंदन से लौटे एक बेटे ने दौलत की खातिर बिस्तर से लगी बूढ़ी मां का जिस तरह कल किया, और जो व्योरे अब सामने आए हैं, वे हतप्रभ करने वाले हैं। 78 साल की बूढ़ी और लाचार महिंदर कौर के यह गुमान में भी नहीं होगा कि जिसे अपनी कोख से जन्म दिया, पाला-पोसा और अपने बुढ़ापे का सहारा के तौर पर देखा, वही उनका कातिल बन जाएगा! वह बूढ़ी मां कितनी तड़पी होगी, प्लैट के गेट तक उसने अपनी जजर काया को कैसे खींचा होगा, यह सोचकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। चंद रोज पहले हुई इस वारदात को आरोपी बेटे ने दुर्घटना बताने की कोशिश की थी, मगर मौका-ए-वारदात के साक्ष्यों ने जांच दल के मन में शुरुआत में ही शुष्णा पैदा कर दिया था, और अब तपतीश के बाद हुए खुलासे इस दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते को कठघरे में खड़ा कर गए हैं। यह पहली वारदात नहीं है, जब किसी बेटे ने ऐसे नृशंस कृत्य को अंजाम दिया हो। नवंबर 2022 में दिल्ली के ही पालम इलाके में एक 25 साल के युवक ने अपने माता-पिता, दादी और बहन की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। मगर इन दोनों अपराधों के बीच जीवन-स्तर, परवरिश, अर्थिक हैसियत और उम्र का एक बड़ा फासला है। पालम कांड का आरोपी बेरोजगार युवा और नशे की गिरफ्त में था, जबकि मानसरोवर गार्डन राजधानी की पॉश कॉलोनियों में शुमार होती है, आरोपी शख्स की उम्र भी दोगुनी है और वह लंदन में अपने दूसरे भाई-बहन के साथ रहता था। ये व्योरे बताते हैं कि हमारे परिवार में खून के रिश्ते भी अब कितने खोखले होते जा रहे हैं और हमें अपने मूल्यों के प्रति किस कदर संवेदनशील होने की जरूरत है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2021 में बिहार में सबसे ज्यादा 815 लोगों की हत्या जमीन व मिल्कियत के लिए हुई, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी हत्याओं का आंकड़ा सैकड़ों में था। जाहिर है, ऐसी ज्यादातर हत्याओं के आरोपी रक्त संबंधी ही होते हैं। इसलिए सरकारों और समाज-शास्त्रियों को इस घातक प्रवृत्ति पर गहन विमर्श करने की जरूरत है मानसरोवर गार्डन की घटना एक अन्य विडंबना को भी उजागर करती है। माता-पिता अपने बच्चों के लिए ऊचे-ऊचे खाब संजोते हैं। उन्हें साकार करने के लिए वे अपनी जिंदगी में तमाम तरह के समझौते करते हैं, लेकिन जब बच्चे किसी अन्य मुल्क में चले जाते हैं, तो उनमें सिर्फ भौगोलिक दूरियां ही नहीं आती, नजरिये में भी फर्क आता है। एक बड़ी संख्या में महिंदर कौरों की जिंदगी तन्हा अपने बच्चों की राह तकते गुजर जाती है। ऐसी अनगिनत गाथाएं इसी अखबार की सुरिखियां बन चुकी हैं, जिनमें परदेसी बच्चों के एकाकी मां-बाप अपने प्लैट या मकान में कंकाल-रूप में बरामद हुए। यह दुराव भूगोल और संसाधनों से अधिक रिश्तों से अपनाइयत के खत्म होते जाने का है। निस्संदेह, सभी बच्चे एक से नहीं होते और हमें अपने बच्चों के लिए बेहतर खाब देखने ही चाहिए, मगर इसके साथ ही उनके भीतर मानवता हमेशा जिंदा रहे, इसका उद्यम भी करते रहना चाहिए। सुदूर मुक्तों में गए अपनों से सवाद बनाए रखें, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराते रहें, ताकि वे हमारे परिवारिक मूल्यों से गाफिल न होने पाएं। श्रवण कुमारों के इस देश में कुप्रुत्र व मारुहंता हमेशा से रहे हैं, मगर ये अपवाद ही रहे, यहीं प्रयास होना चाहिए।

आज का राशीफल

मेष	अर्थिक योजना सफल होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा देशानन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।
वृषभ	जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। न और अनुबंध प्राप्त होंगे। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।
मिथुन	परिवारिक जीवन सुखमय होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। किसी रिशेदार के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। किंजलखर्चों पर नियंत्रण रखें। अपनों से तनाव मिलेगा।
कर्क	व्यावसायिक योजना सफल होगी। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आय और व्यय में एक संतुलन बना कर रखें अन्यथा कर्ज की स्थिति आ सकती है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।
सिंह	प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। धन लाभ की संभावना है। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।
कन्या	परिवारिक जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। स्थानान्तरण व परिवर्तन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें।
तुला	व्यावसायिक तथा अर्थिक प्रयास सफल होंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी।
वृश्चिक	अर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अनावश्यक खर्चों का सामना करना पड़ेगा। पिता या उच्चाधिकारी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यर्थ की भागदौड़ होगी।
धनु	व्यावसायिक तथा अर्थिक योजनाएं सफल होंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। खन-पान में संयंसर रखें। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। विरोधियों का पराभव होगा।
मकर	परिवारिक जनों से पीड़ा मिल सकती है। संतान के संबंध में चिंतित रहेंगे आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। उदार विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। प्रियजन पीड़ा मिल सकती है।
कुम्भ	जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। यात्रा देशानन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। विचारोंधी परास्त होंगे।
मीन	गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यात्रा में अपने सामन के प्रति सचेत रहें, चारों या खोने की आशंका है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। किंजलखर्चों पर नियंत्रण रखें।

विचारमंथन

(लेखक - सनत जैन)

सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने की 21 याचिकाओं की सुनवाई चल रही है। इस खंडपीठ में मुख्य न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एसके कोल, न्यायमूर्ति एसआर भट्ट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पीएस नरसिंहा शामिल हैं। सुनवाई शुरू होने के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिस्टर जनरल तुशर महेता ने अदालत से कहा, इस या चिका के मुद्दे को तय करने का अधिकार संसद के पास है। अदालत इसे नहीं सुने। उन्होंने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ लोगों के जिरह में शामिल होने का यह मतलब नहीं है, कि वह अन्य लोगों

हाइड्रोजन मिशन से पर्यावरण लक्ष्य पाने की व्यवहार्यता

प्रीतम सिंह, साइमन पिरानी

केंद्रीय सरकार द्वारा गत जनवरी में अपनाया गया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक प्रमुख नीतिगत पहल है, और इसे भारतीय राजनीति की कमी ही कहेंगे कि इस नीति पर जितनी सार्वजनिक बहस की जानी बनती थी, वह नहीं हो पायी। इस पहल पर, भारत की विपक्षी पार्टियों के आलोचनात्मक मूल्यांकन की अनुपस्थिति, जिसका भारत के प्रगति पथ पर काफी असर हो सकता है, हेरानीजनक। सरकार उन कंपनियों को सब्सिडी देने की पेशकश कर रही है जो हाइड्रोजन हब स्थापित करेंगी, लेकिन यह काम किस तरह से पर्यावरण नीति और सामाजिक न्याय ध्येय के अनुरूप है, इसकी व्याख्या होना बाकी है। हाइड्रोजन मिशन के मुताबिक, बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस और झाड़ियन अॅयल को इस मद में रखे गए 20000 करोड़ का फंड पाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इलेक्ट्रोलॉज़र बनाने के लिए ऐसा अनुमति दिया जाएगा, जो कि ऐसी व्यवस्था का बनाने के लिए आवश्यक है।



के लिए जरूरी है, फिर खाद एवं स्टील उत्पादकों को इन्हें खरीदने के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। लेकिन जिस अति उत्साह और जोर-शोर से हाइड्रोजेन मिशन का ऐलान किया गया है, वह गैर-वाजिब उम्मीदें बढ़ाता है। दरअसल, विदेश मंत्रालय का हालिया दावा कि भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजेन हमारी ऊर्जा जरुरतों का मुख्य स्रोत रहेगी, शायद ही कभी फलीभूत हो पाए। यदि सरकार 10 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजेन प्रति वर्ष बनाने का ध्येय पूरा कर भी ते, तो भी यह कोयले से प्राप्त ऊर्जा का 15वां हिस्सा भर होगा। सरकारी फाइलों में सरपट दौड़ रहे इस विचार कि भारत हाइड्रोजेन का मुख्य निर्यातक भी बन जाएगा, पर भी संशय है। यदि खाद निर्माण और तेल रिफाइनरी में प्रयुक्त मौजूदा ग्रे हाइड्रोजेन को हरित हाइड्रोजेन से बदलना है तो भारत को हर साल 60 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजेन की जरुरत पड़ेगी। ग्रे-हाइड्रोजेन का उपयोग बंद करना एक प्राथमिकता है, यह वैश्विक तापमान बढ़ोत्तरी में दुःख्यन की तरह है क्योंकि प्रत्येक उत्पादित ग्रे-हाइड्रोजेन के पीछे 10-18 टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में घुलती है हाइड्रोजेन निर्यातक बनने का सपना पालने से पहले, भारत को यह भी आकलन करना होगा कि क्या प्रतिवर्ष 16 करोड़ टन कोयले के उपयोग और 30 बिलियन वर्ष्युविक मीटर आयातित गैस के विकल्प लायक मात्रा बनाना संभव भी है। ग्रीन हाइड्रोजेन इलेक्ट्रोलिसिज़ नामक प्रक्रिया से बनती है- इसमें पानी में करंट छोड़ा जाता है- इसके लिए बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों, जैसे कि पवन या सौर अथवा जल ऊर्जा से पाने की योजना है। तभी तो इस प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैस का सीधा उत्सर्जन नहीं होगा, हालांकि मूल अवयव के तौर पर बिजली और पानी बहुत प्रचुर मात्रा में लगता है। हाइड्रोजेन बनाने की तुलनात्मक लागत और स्रोतों पर पड़ने वाले असर को लेकर एक सार्वजनिक बहस फौरी तौर पर की जाने की जरुरत है, यह इस पर भी होनी चाहिए कि क्या हाइड्रोजेन पर निवेश करने से हमें मौसम में हो रहे बदलावों और सामाजिक असमानता को थामने में मदद मिलेगी। लागत की बात करें तो केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्रालय का दावा है कि वर्ष 2026 से पहले ही ग्रीन हाइड्रोजेन वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजेन की कीमत 2 डॉलर प्रति किलोग्राम तक यहां शब्द 'शायद' है न कि 'पछा'। विश्लेषक एंजेंसी सीआरयू का कहने ग्रीन हाइड्रोजेन की कीमतें 2050 तक से नीचे आ पाएं। विगत में भी बाजार में बदलावों से निपटने में विफल रहा कि एक बार पुनः असफल हो सकता है। यह दावा करता है कि भारत अक्षय बिजली निर्यात कर पाएगा लेकिन उस वाले ऐसे दावों के प्रति सावधानी बरकरार रखना चाहिए। अॉफ रेग्यूलेशन के अनुसंधान नेशनल ग्रीन प्रिड मिशन को चालू रखना चाहिए। 50 बिलियन लीटर लवण्यमुक्त पानी भारत के अनेक भाग पहले ही जल रिसोर्स इस्टिट्यूट (टेरी) के विश्लेषण भूमि की कमी भी सौर एवं पवन जल की बनेगी। इलेक्ट्रोलाइज़र का सीमित उपयोग वजह रहेगा। फिलहाल, विश्व के इस साल 8 गीगावॉट ऊर्जा बनाने जितनी जरुरत है। इस हिसाब से 12 साल तो जबकि स्वदेशी इलेक्ट्रोलिसिस क्षमता सावल यह भी कि खतरनाक मौसम योगदान के लिए क्या भारत हाइड्रोजेन के विकल्प के रूप में अक्षय ऊर्जा हाइड्रोजेन मिशन का ध्येय है 2030 तक उत्पादन प्रति वर्ष 5 लाख टन ले जाने की जरुरत पड़ेगी। इसका मतलब कि से जितनी ऊर्जा भारत फिलहाल प्राप्त होगा। लेकिन यह कहना कि ग्रीन हाइड्रोजेन बनाने से भारत 30-40 कोयला 3

सेवामुक्त कर पाएगा और इससे कोयला जलाने और कोयले का आयात घटाने, वैश्विक तापमान बढ़ोतरी और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, अभी दूर की कौड़ी है। टेरी की एवं रिपोर्ट कहती है - अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करके हाइड्रोजेन बनाना ऊर्जा-खपतकारी प्रक्रिया है। जहां तक संभव हो परोस विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह इसलिए भी क्योंकि यदि आप ऊर्जा की 10 यूनिट (बिजली) ग्रीन हाइड्रोजेन बनाने में इस्तेमाल करते हैं तो यूं बनकर मिली हाइड्रोजेन बिजली की 7 यूनिट ऊर्जा के बराबर होगी। यदि इसे दूसरे जगह ले जाने को सम्पीड़ित करें तो इसमें बिजली की 3 यूनिट और खपेंगी। ऐसे में बिजली को पहले हाइड्रोजेन में तब्दील करके की बजाय सीधा इस्तेमाल करना ऊर्जा-दक्षता के हिसाब से सब ज्यादा व्यावहारिक होता है। विशेषज्ञ राय के बाबजूद, हाइड्रोजेन उत्पादकों की बनाई बिजली को तरजीह देकर खरीदने का पेशकश की जा रही है। होना तो यह चाहिए कि खतरनाक पर्यावरण बदलावों को नाथने की लड़ाई उन नीतियों के साथ हाल मिलाकर चले जो सामाजिक असमानता का भी हल निकालते हों। भारत के हाइड्रोजेन को लेकर उत्साही पक्ष में रिलायंस इंडस्ट्री भी एक है, जो ऑस्ट्रेलिया में इसके उत्पादन में निवेश करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा इंडियन ऑयल कंपनी है जिसका कहना है कि अगले दशक तक जो भी हाइड्रोजेन यह बनाएगी, उसमें आधे से ज्यादा हिस्सा ग्रीन हो। पिछले साल, अडानी ग्रुप ने भी फांस की कंपनी टोटल एनर्जी वेल्स साथ मिलकर 50 बिलियन डॉलर हाइड्रोजेन संवर्धन में लगाने की घोषणा की थी। लेकिन हिंडनवर्ग प्रसंग के बाद यह ठंडे बरसे गए है। दरअसल, पर्यावरण और विकास ध्येयों की पूर्ति के लिए हाइड्रोजेन का इस्तेमाल करने में उक्त विषयों का हल निकालना जरूरी है।

प्रीतम सिंह ऑक्सफोर्ड ब्रूकस बिज़िनेस स्कूल में प्रोफेसर एमीरेटस हैं और साइमन पिरानी, यूनिवर्सिटी ऑफ डरहैम, यूवे में मानद प्रोफेसर हैं।

शब्दों की असीम शक्ति से संवारिये ज़दिगियाँ

अंतर्मन/ योगेन्द्र नाथ शर्मा 'अरुण'

समाज में आज सर्वत्र आपको ऐसे लोग सरलता से मिल जाएंगे, जो बिना कारण आपको हतोत्साहित करके आपके कार्य से विमुख करना चाहेंगे। आप कोई परीक्षा देना चाहें और आपके आसपास के किसी व्यक्ति को इस का पता चल जाए, तो आते ही भाषण देने लगेगा कि यार तुम भी क्या सटिया गए हो? अब परीक्षा देने की भला क्या तुक है? मजा करो, फेल हो जाओगे तो बेकार में बदनामी और जगह-साई होगी। हिम्मत बंधाना तो दूर की बात है, वे हजार बुराइयाँ और मुसीबत निकाल देंगे। ऐसे तो बस, विरले ही मिलते हैं, जो आपकी तारीफ करें और कहें कि बहुत अच्छी बात है। कोई मुश्किल हो तो हम मदद करेंगे, परीक्षा जरूर दो। मनोविज्ञानी कहते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अकारण 'विघ्न संतोषी' होते हैं। मध्यरा की तरह उन्हें किसी की खुशी अच्छी ही नहीं लगती। ये व्यक्ति वस्तुतः अकर्मण्य होते हैं और इनका चिंतन समाज में सदैव नकारात्मक ही रहता है। ये खुद तो जीवन में कभी सफल हो नहीं पाते, इसीलिए किसी और की सफलता इन्हें कठतई नहीं सुहाती। आज मुझे एक बड़ी ही रोचक और प्रेरक बोध-कथा पढ़ने को मिली, जो ऐसे ही विघ्न संतोषियों के चरित्र को उजागर करती है और सिद्ध करती है कि किसी के सकारात्मक शब्द जीवन में कैसे संजीवनी बन जाते हैं। यह बोध-कथा इस प्रकार है :- 'एक नौजवान चीता पहली बार जंगल में शिकार करने निकला। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक चालाक लकड़बग्धा आया और उसे रोकते तो आज पहली बार अकेले अपने दम पर शिकार करने निकला हूँ!' नौजवान चीता बहुत रोमांचित होते हुए बोला। चालाक लकड़बग्धा उपरी से बोला— 'छोटू जी! अभी तो तुम्हारे खेलने-कूदने के दिन हैं। तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें शिकार करने का कोई अनुभव भी तो नहीं है। तुम भला क्या शिकार करोगे?' लकड़बग्धे की बात सुनकर युवा चीता उदास हो गया। दिनभर शिकार के लिए वो बेमन इधर-उधर घूमता रहा। उसने कुछ एक प्रयास भी किये, पर सफलता नहीं मिली और उसे भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगली सुबह वो एक बार फिर शिकार के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक उदारमना बूढ़े बन्दर ने देखा और पूछा 'कहां जा रहे हो बेटा?' 'बंदर मामा, मैं आज अकेले शिकार पर जा रहा हूँ।' चीता उत्साह में भर कर बोला। बंदर मामा युवा का उत्साह देख प्रसन्न होकर बोला, 'बहुत अच्छे। अपने बाप की तरह तुम में भी खुब ताकत और गति है। इनके कारण तुम तो बेहद कुशल शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जंगल में जल्द ही बड़ी सफलता मिलेगी।' बूढ़े बंदर मामा की यह बात सुनकर युवा चीता उत्साह से भर गया और कुछ ही समय में उसने एक छोटे हिरन का शिकार कर लिया। आज उसे अपनी ताकत का अहसास हो गया और उसका आत्मविश्वास लौट आया।' सच मानिए!



हमारी जिन्दगी में 'शब्द' बहुत महत्व रखते हैं। दोनों ही दिन चीता तो वही था, उसमें वही फूर्ति और वही ताकत थी, लेकिन जिस दिन उसे चालाक लगड़बग्धे द्वारा हतोत्साहित किया गया, उस दिन वो असफल हो गया और जिस को भी 'हतोत्साहित' कदापि न करें, बल्कि सहयोगी बनकर हिम्मत बढ़ाएं। साथ ही, हम ऐसे लोगों से बचें, जो हमेशा नेगेटिव सोचते और बोलते हों। समाज में उनका साथ करें जिनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो। हमें सोचने

‘शब्द ‘ब्रह्म’ हाता सख, शाक्त लिए अपार साहस जब दे शब्द तो, बदल जाय संसार।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उसकी हृद बताई

का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले न्यायालय को यह तय करना चाहिए कि उसे सुनवाई का अधिकार है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जज काफी नाराज हुए। उनका कहना था कि आप हमें नहीं बता सकते हैं कि हमें किस मामले की सुनवाई करनी है, या नहीं करनी है। या चिका पर फैसला किस तरह से करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सही वक्त आने पर आपको भी सुनेंगे, सभी पक्षों को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेंगी। पिछले 8-9 वर्षों में सरकार के अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में न्यायालय की अधिकारिता, राष्ट्रीय सुरक्षा ओर गोपनीयता को आधार बनाकर न्यायालय से बचने का प्रयास करती है। पिछले कई तर्जों में सरकार न्यायालय इस तरह से दलील देकर जिम्मेदारी से बचती रही। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीव घंटवृद्ध के बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुद्ध बदला हुआ नजर आ रहा है। न्यायालय में जो कोई भी पक्ष या चिका लेकर आता है, उसका सुनना है या नहीं, यह अधिकार न्यायालय तक है। नाकि सरकार का है। संसद और न्यायपालिका के अधिकार अलग-अलग हैं। संसद कानून बना सकती है। उसकी समीक्षा का अधिकार संघ विधान ने न्यायपालिका द्वारा ही दिया है। संसद में बहुत सारे कानून भी इतन्त्र के दबाव में सरकार बना देती हैं। कानून एवं उसके नियम संविधान और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। इसको देखने का काम न्यायपालिका का है। विधायिका और कार्यपालिका को संविधान

असीम शक्तियां दी हैं। वह अपने कामकाज को सर्वैधानिक तरीके से करें। न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून और नियमों के तहत कार्य किया जा रहा है या नहीं इसकी समीक्षा का अधिकार केवल न्यायपालिका का है। न्यायपालिका की सीमा सरकार तय नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपा लिका के अधिकार सरकार को अच्छे तरीके से समझा दिया है। गुजरात सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के मांगने के बाद भी बिलिकिस बानो प्रकरण के अपराधियों को जेल से समय पूर्व छोड़े जाने और पैरोल दिए जाने के मामले की फाइलें तलब की थी। लेकिन गुजरात सरकार फाइलें प्रस्तुत नहीं कर रही थी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कठी लताड़ लगाते हीने गुजरात सरकार को अत्यन्तान्त्रिकी

र्वर्वाई करने की चेतावनी देनी पड़ी। पिछले छ वर्षों में बंद लिफाफे, सरकार की वर्चता, न्यायाधीशों की नियुक्ति, सविधान से पर विधायिका की आड़ लेकर न्यायपालिका का कमजोर करने का प्रयास लगातार हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में न्यायपा लिका की थित में सुधार आ रहा है। न्यायपालिका का एष रूप से मानना है कि जब दो पक्ष न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तब इसमें पनीयत जैसी कोई बात नहीं होती है। न्यायपालिका, सविधान-कानून और नियम के नुसार ही सुनवाई कर निर्णय करती है। सरकार सत्य को छुपाना चाहती है। इसे सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्ट नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस रुख से लोगों का एक बार फिर न्यायपालिका के ऊपर विश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि न्यायपालिका के खिलाफ, मंत्रियों और उपराष्ट्रपति द्वारा जो बयान समय-समय पर दिए गए थे, उस पर न्यायपालिका द्वारा कभी कोई टिप्पणी नहीं की। उल्टे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पारदर्शिता का पाठ पढ़ाने के लिए कॉलेजियम द्वारा जांच की नियुक्ति की प्रक्रिया को सार्वजनिक करके उल्टे सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। न्यायपालिका के रुख से अब लोगों को विश्वास होने लगा है कि उसे न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। न्याय के लिये न्यायपा लिका के लिये सभी पक्ष समान है। हर मामले में सत्यता को छिपाने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की आड़ नहीं ली जा सकती है।



नैनीताल जा रहे हैं तो ये 5 जगह देखना न भूलें

बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच झीलों से घिरा नैनीताल उत्तराखण्ड राज्य का प्रसिद्ध हनीमून स्पॉट है। नैनी शब्द का अर्थ है आंखें और 'ताल' का अर्थ है झील। यहां आकर आपको शांत और प्रकृति के पास होने जैसा महसूस होगा। यहां चारों ओर खूबसूरती विखरी है। सैर-सपाटे के लिए दर्जनों जगहें हैं, जहां जाकर पर्षटक हैरान रह जाते हैं और प्राकृतिक नजारों को बस देखते ही रहते हैं। आओ जानते हैं यहां के प्रमुख स्पॉट।

नैनीताल घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून

1. नैनीताल नैना झील :

यहां कि प्रसिद्ध झील नैना झील है जिसे ताल भी कहा जाता है। ताल में बहतों के झूँड, रंग-बिरंगी नौंसें और ऊपर से बहती ठंडी हवा यहां एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। ताल का पानी गर्मियों में हरा, बरसात में मटमैला और सर्दियों में हल्का नीला दिखाइ देता है। एक समय में नैनीताल जिले में 60 से ज्यादा झीलें हुआ करती थीं।

2. नैना देवी मंदिर :

इसे नैनीताल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर ऊंचे पहाड़ पर नैना देवी का एक मंदिर है।

3. हिल स्टेशन :

बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच झीलों से घिरा नैनीताल उत्तराखण्ड राज्य का प्रसिद्ध हनीमून स्पॉट है। यहां टॉप पर नैना चोटी, स्नो व्यू और टिफिन टॉप हैं। स्नो व्यू पर आप रोपें से जा सकते हैं।

4. प्राणी उद्यान नैनीताल :

पठित जीवी पंत प्राणी उद्यान यहां के प्रसिद्ध स्थल है। गोविंद बल्भ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान नैनीताल बस स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

5. हनुमानगढ़ी नैनीताल :

यह यहां का धार्मिक स्थल है जो मुख्य शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर है।

इसके अलावा गवेनर हाउस है और शॉपिंग के लिए आप मार्केट मॉलरोड जा सकते हैं।



अल्मोड़ा भारत के उत्तराखण्ड राज्य का एक बहुत ही सुंदर नगर है। इसके पूर्व में पिथौरागढ़ व चम्पावत, पश्चिम में पौड़ी, उत्तर में बागेश्वर, दक्षिण में नैनीताल स्थित है। अल्मोड़ा में मनोरम पहाड़ी और घाटियां हैं जो आपका दिल मोह लेगी। यदि आप यहां जाने का प्लान कर रहे हैं तो जान लें इस क्षेत्र के बारे में दिलचस्प जानकारी।

अल्मोड़ा हिल स्टेशन

1. अल्मोड़ा में कई मंदिर हैं। दूनामिरी मंदिर, कसरार देवी मंदिर, विताई गोलू मंदिर, नंदादेवी मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, जागेश्वर धाम मंदिर आदि कई बहुत ही सुंदर और धैतन्य मंदिर हैं। यहां अंग्रेजों के काल का बोडेन मेमोरियल मेथाडिटर चर्च भी है।

2. अल्मोड़ा में घूमने लायक जगह जीरो पाइंट बहुत ही अद्भुत है जो बिनसर अभ्यारण्य में बहुत कंचाई पर स्थित है। यहां से आसमान को देखना बहुत ही रोमांचित कर देगा। यहां से केदारनाथ और नंदादेवी की चोटी को देखना तो आपके आश्वर्य और रोमांच को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। यहां से हिमालय की वादियों का दृश्य आपको स्वर्ण में होने का अहसास देगा।

3. अल्मोड़ा से 3 किलोमीटर दूर जलना एक छोटासा पहाड़ी गांव है जहां से आप प्रकृति और एकांत का आदंद ले सकते हैं। यहां पर 480 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां, वनस्पतियों की एक विस्तृत श्रृंखला और तितली संग्रह से भरे जंगल पाए जाते हैं।

4. अल्मोड़ा से 3 किमी दूर स्थित, ब्राइट एंड कॉर्नर पाइंट से आप सूर्योर्धन और सूर्योदय के लुभावने दृश्य देखकर रोमांचित हो उठेंगे। यह एक विशेष बिंदु है जहां से हिमालय के अविश्वसनीय दृश्य देख सकते हैं। हिमालयी चोटियों में जैसे क्रिशल I, क्रिशल II, क्रिशल III, नंदादेवी, नंदकोट, पंचायूली इत्यादि को देख सकते हैं।

5. अल्मोड़ा कुमाऊं पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह माउंटेन बाइकिंग के लिए भारत में सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। और यदि यदि आप रिवर रापिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो काली शारदा नदी जाना होगा।

6. अल्मोड़ा कुमाऊं पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह नंदादेवी चोटी की चोटी से ही हो जाती है जो नीचे चाटी तक आती है। आओ जानते हैं नंदा देवी की ऐतिहासिक यात्रा की 10 खास बातें।

7. नंदा देवी की चोटी : नंदा देवी की चोटी एक अत्यधिक कठिन मानी जाती है। नंदा देवी की कुल ऊंचाई 7816 मीटर यानी 25,643 फैट है। यहां तक पहुँचने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में एक धार्मिक यात्रा का आयोजन होता है जो प्रतिवर्ष भाद्रपद के शुरुआत पक्ष में नंदादेवी मेला ग्रांथम होता है।

8. नंदा देवी की चोटी : नंदा देवी की कुल ऊंचाई 7816 मीटर यानी 25,643 फैट है। यहां तक पहुँचने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में एक धार्मिक यात्रा का आयोजन होता है। यहां कई प्रजातियों के जीव-जंतु रहते हैं। इसकी सीमाएं चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों से जुड़ती हैं।

9. नंदा देवी की चोटी : नंदा देवी की कुल ऊंचाई 7816 मीटर यानी 25,643 फैट है। यहां तक पहुँचने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में एक धार्मिक यात्रा का आयोजन होता है। यहां कई प्रजातियों के जीव-जंतु रहते हैं। इसकी सीमाएं चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों से जुड़ती हैं।

10. नंदा देवी की चोटी : नंदा देवी की कुल ऊंचाई 7816 मीटर यानी 25,643 फैट है। यहां तक पहुँचने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में एक धार्मिक यात्रा का आयोजन होता है। यहां कई प्रजातियों के जीव-जंतु रहते हैं। इसकी सीमाएं चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों से जुड़ती हैं।

11. नंदा देवी की चोटी : नंदा देवी की कुल ऊंचाई 7816 मीटर यानी 25,643 फैट है। यहां तक पहुँचने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में एक धार्मिक यात्रा का आयोजन होता है। यहां कई प्रजातियों के जीव-जंतु रहते हैं। इसकी सीमाएं चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों से जुड़ती हैं।

12. नंदा देवी की चोटी : नंदा देवी की कुल ऊंचाई 7816 मीटर यानी 25,643 फैट है। यहां तक पहुँचने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में एक धार्मिक यात्रा का आयोजन होता है। यहां कई प्रजातियों के जीव-जंतु रहते हैं। इसकी सीमाएं चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों से जुड़ती हैं।

13. नंदा देवी की चोटी : नंदा देवी की कुल ऊंचाई 7816 मीटर यानी 25,643 फैट है। यहां तक पहुँचने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में एक धार्मिक यात्रा का आयोजन होता है। यहां कई प्रजातियों के जीव-जंतु रहते हैं। इसकी सीमाएं चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों से जुड़ती हैं।

14. नंदा देवी की चोटी : नंदा देवी की कुल ऊंचाई 7816 मीटर यानी 25,643 फैट है। यहां तक पहुँचने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में एक धार्मिक यात्रा का आयोजन होता है। यहां कई प्रजातियों के जीव-जंतु रहते हैं। इसकी सीमाएं चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों से जुड़ती हैं।

15. नंदा देवी की चोटी : नंदा देवी की कुल ऊंचाई 7816 मीटर यानी 25,643 फैट है। यहां तक पहुँचने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में एक धार्मिक यात्रा का आयोजन होता है। यहां कई प्रजातियों के जीव-जंतु रहते हैं। इसकी सीमाएं चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों से जुड़ती हैं।

16. नंदा देवी की चोटी : नंदा देवी की कुल ऊंचाई 7816 मीटर यानी 25,643 फैट है। यहां तक पहुँचने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में एक धार्मिक यात्रा का आयोजन होता है। यहां कई प्रजातियों के जीव-जंतु रहते हैं। इसकी सीमाएं चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों से जुड़ती हैं।

17. नंदा देवी की चोटी : नंदा देवी की कुल ऊंचाई 7816 मीटर यानी 25,643 फैट है। यहां तक पहुँचने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में एक धार्मिक यात्रा का आयोजन होता है। यहां कई प्रजातियों के जीव-जंतु रहते हैं। इसकी सीमाएं चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों से जुड़ती हैं।

18. नंदा देवी की चोटी : नंदा देवी की कुल ऊंचाई 7816 मीटर यानी 25,643 फैट है। यहां तक पहुँचने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में एक धार्मिक यात्रा का आयोजन होता है। यहां कई प्रजातियों के जीव-जंतु रहते हैं। इसकी सीमाएं चमोली, पिथौरागढ़ और बाग

संभल। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस करड़ी में हत्या पास सपा सांसद डॉकटर शफीकुर्रहमान बर्क ने तीर्खी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीधे-सीधे यूपी सरकार पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा विधुयी में सुरक्षा नहीं, मुख्ल में इंसाफ नहीं तो अदालतें बंद कर देना चाहिए। सपा सांसद ने जेल में बंद अतीक के दोनों नाबालिग बच्चों की सरकार से सुरक्षा की गारंटी मांगी। सांसद ने कहा कि पुलिस और अदालत कानून सब कुछ है। हमारे पास पुलिस की करड़ी में किसी को मारा जाएगा तो अदालत की कथा जरुर रखें। हमें अदालत पर बैकर हो गई, उनका कथा असर होगा। उनके साथ जुर्म हुआ है। कानूनी इंसाफ नहीं मिला, जब होता चाहे उनको सजा-ए-मौत होती, चाहे उनको फांसी पर लटकाया जाता। जो कुछ भी होता उसके लिए अदालत मौजूद है। हमारे पास कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है। अदालत बनी हुई है अदालत को उनके केस का भेजना चाहिए था। अब तो जुर्म की इंतहा हो गई है कानून तो इतनी ताकत नहीं देता, जिसको चाहें, जिससे मरवा दें। सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया था। उन्होंने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली है, अदालत भी अपनी ताकत का इस तरह इस्तेमाल नहीं करती। सांसद बर्क ने कहा कि योगी सरकार अतीक वे परिवार के साथ जातीय दुर्मनी निभा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्ल में इंसाफ और सजा के लिए देश का कानून है। सपा सांसद ने कहा कि वह लेटर टेस्ट मिल चुका है, उन्होंने इंसाफ मांगा था। पुलिस करड़ी में लाए फिर कैसे मार गए। वह यूपी और सेंटर दोनों की बड़ी लापरवाही है। असली तो यूपी की है यूपी सरकार की नियत सही नहीं है। अतीक और अशरफ को तो मार दिया गया, लेकिन उसके दोनों नाबालिग बच्चों की सुरक्षा की जाए। बीते शनिवार रात को अतीक और अशरफ को मैटिकल टेस्ट के लिए अस्पताल लाया जा रहा था। इस दौरान पत्रकार बनकर आए तीन युवकों ने दोनों भाइयों पर ताबड़तों गोलियां बरसा दीं, जिससे दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

इंडिगो एयरलाइन में मच्छरों का आतंक, यात्रियों ने की शिकायत

**केजरीवाल सहित आठ मुख्यमंत्री आ चुके हैं
सीबीआई जांच के घेरे में**

नई दिल्ली। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कौन किसका दोस्त और शत्रु बन जाता है कहा नहीं जा सकता। यह सब देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। यही स्थिति जननेताओं की है। भरपूर मत व समर्थन के बावजूद भी सरकार चलाने वाले जनप्रतिनिधि कभी-कभी ऐसी चूंक कर जाते हैं कि उन्हें सीधीआई के समक्ष हाजरी देनी पड़ जाती है। कई बार यह राजनीति से प्रेरित होती है तो कई बार भ्रष्टाचार का मामला होता है। गौरतलब है कि बीते तीन दशकों में सीधीआई के समक्ष पेश होने वाले मुख्यमन्त्रियों में उत्तर प्रदेश के नेताओं की संख्या सर्वाधिक है। सूची में उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमन्त्री बने अखिलेश यादव सहित अन्य तीन मुख्यमन्त्रियों में उनके पिता और समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व कद्दावर नेता कल्याण सिंह शामिल हैं। इसके अलावा चारा घोटाले में विहार के मुख्यमन्त्री लाल यादव और उनकी पत्नी राधाड़ी देवी मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह वीहान तथा हाल ही में दिल्ली के मुख्यमन्त्री अरविंद केजरीवाल भी इस सूची में शामिल हो गए। हाल ही में कथित शराब नीति मामले में सीधीआई ने दिल्ली के मुख्यमन्त्री अरविंद केजरीवाल को पछालाछ के लिए बूलाया। सीधीआई ने लगभग साढ़े 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की। गौरतलब है कि केजरीवाल के नेतृत्व में फरवरी 2015 के चुनावों में उनकी पार्टी ने 70 में से रिकॉर्ड 67 सीटें जीतकर भारी बहमत हासिल किया और 14 फरवरी 2015 को वह दोबारा दिल्ली के मुख्यमन्त्री बने। 16 फरवरी 2020 से वे तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमन्त्री पद पर आसीन हैं। उल्लेखनीय है कि शराब नीति में कथित फेरबदल को लेकर आप पार्टी के नेता व दिल्ली सरकार के उप-मुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया पहले से रामलाल हान पारा यूप मुख्यमन्त्री जगदारा राहर का नाम पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। राजस्थान के मुख्यमन्त्री अशक्क गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल और हिमाचल के मुख्यमन्त्री सूची में शामिल रहने वाले साचिन पायलट का नाम इस सूची से बाहर है। इसको लेकर भी भी तरह-तरह की अटकलें चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि साचिन पायलट के अनशन की वजह से आलाकमान नाराज

सूची में शामिल रहने वाले साचिन पायलट का नाम इस सूची से बाहर है। इसको लेकर भी भी तरह-तरह की अटकलें चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि साचिन पायलट के अनशन की वजह से आलाकमान नाराज

मुख्यमन्त्री बाएंस बादबुधा, राज्य के माजपा प्रमुख नलिन कुमार कठील, मुख्यमन्त्री बसवराज जोमाई भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची में जौद है।

फैक्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को रामलला का जलाभिषेक करेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ राजनयिक, धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं के साथ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा आमत्रित करने की तैयारी है।

ईद और परशुराम जयंती से पहले सुरक्षा के प्रब्लेम्स दंतजाम अलर्ट पर रहेगी यांची पलिस

लखनऊ। प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों के त्रैम में गूरुवार को प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक आरके विश्वकर्मा व स्पशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार द्वारा सभी एडीजी जोन, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिशनर, आईजी, डीआईजी, एसएसपी/एसपी आदि के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। वीडियो कॉफ़िरिंग के माध्यम से हीबैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि हालिया वर्षों में प्रदेश में सभी धर्मों के पर्व और त्योहार शांति और सौहार्द के माहौल के बीच संपर्क हुए हैं। इसके पारे देश में एक अच्छा सदेश गया है। प्रदेश में हर एक नागरिक की सुरक्षा हम सभी का प्राथमिक दायित्व है। हमें अपने इस दायित्व के प्रति संदेश सतर्क-सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना चल रहा है। आगामी 22 अप्रैल को ईंट-उल-फिरत, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती का पर्व एक ही दिन होना संभावित है। वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा।

अनुरोध दोहराता है, क्योंकि यह मुद्दा स्पष्ट रूप से उनके विधाई दायर में आता है, और उसके बाद ही माननीय न्यायालय में इस मुद्दे पर फैसला किया जाए। हलफनामे में कहा गया है कि भले ही वर्तमान मामला और इस अदालत द्वारा परिधापित मुद्दा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 तक सीमित हो, इसके लिए विवाह नाम के एक कथित अलग सामाजिक संस्था के नायिक निर्माण की जरूरत है जो मौजूदा कानूनों से पौर है। इसमें आगे विनप्रतापूलक अनुराध किया जाता है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वर्तमान कार्यवाही में एक पक्षकार बनाया जाए और उनके संबंधित रुख को रिकॉर्ड में लिया जाए और विकल्प के रूप में, भारत संघ को राज्यों के साथ परामर्श प्रक्रिया पूरी करने, उनकी राय/आशंकाएं जानने और इन्हें संकलित कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी जाए। उसके बाद ही वर्तमान मुद्दे पर निर्णय लें।

पाल पालाणा। मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने सारस के संरक्षण के लिए कार्यवोजना बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में यूपी में आरिफ नाम के शख्स द्वारा सारस पालने का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। आरिफ को अगस्त 2022 में घायल अवस्था में एक सारस मिला था। आरिफ ने उसका इलाज किया, तब से सारस उसके साथ रहने लग गया और वो जहां भी जाता सारस उसके साथ ही जाता था। यह मामला तब ज्यादा चर्चा में आया था, जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों के किससे सुनकर आरिफ से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद

के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। राज्य वन्य जीव बैर्ड की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के राज्य पशु ‘बारहसिंधा’ और राज्य पक्षी ‘सारस’ के संरक्षण के लिए नियोजित प्रयास करने होंगे। इस संबंध में कार्यवोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने इस बैठक में कहा कि यह सुखद है कि नमामि गणे परियोजना के माध्यम से अविरत और निर्मल हो रहीं गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतारी हुई है। बैठक में कुकरैल नाईट सफारी, लखनऊ और रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, इस संबंध में वन्य जीव

भारत में भीषण गर्मी के कारण काम करने के दृंटों में आ सकती हैं कमी

संस्कृत साहित्य में 145 दिन साथे

नई दिल्ली (एजेंसी)। भीषण गर्मी और तपती धूप से भारत में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में लोगों के काम करने की क्षमता पर प्रतिशत का संकेत है, इनका तुलना 2.2 अवधिक गर्मी से काम के घंटों में नुकसान 1 प्रतिशत से कम रह सकता है। आईएलओन रिपोर्ट, 2019 में कहा गया है कि गर्म मौसम से कृषि क्षेत्र पर सर्वाधिक असर देता है। एक्स्प्रेस ने जारी की एक रिपोर्ट में इन तरफ से उल्लेख किया है कि देश के ज्यातातर राज्य अवसर अवधिक गर्मी में ज्ञाल से रहे हैं। पिछले 12 साल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अवधिक गर्मी बाले दिनों की संख्या (145) सबसे अधिक रही। आधुनिक प्रदेश में इस तरह के दिनों की संख्या 111 तक चढ़ी है, जब से पहले

असर हो सकता है। इसके साथ ही भीषण गर्मी से मानवीय स्तर पर भी नुकसान हो सकता है।

महाराष्ट्र में हुई घटना इसी ओर इशारा करती है। राज्य में एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने आए करीब एक दर्जन लोगों को मौत लूँगने से हुई और सैकड़ों लोग अस्तपाल में भर्ती किए गए। एक अनुमान के अनुसार 2030 तक भीषण गर्मी से भारत में काम के कुल घटे 6 प्रतिशत तक कम हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय त्रिम संगठन (आईएलओ) के अनुसार भारत की तुलना में दुनिया के शेष हिस्से में गर्म हवाओं एवं अत्यधिक गर्मी से काम के घटे शेषे कम होगा, वहाँ निमाण क्षत्र में काम के घट खास कम हो जाएगा।

काम करने के घटे में कमी 3.4 करोड़ पूर्णकालिक नौकरियाँ जाने के समतुल्य हैं। चीन और अमेरिका में यह आंकड़ा थोड़ा कम है। संसद में प्रस्तुत 18 राज्यों से जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार लूँवाले एवं अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक राज्य में अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है। 2011 में इसतरह के दिनों की कुल संख्या 40 थी। यह संख्या 2022 में बढ़कर 203 हो गई। इनमें कछुदिनों की संख्या घट-घट दाना का संख्या 111 रही और तब से राज्य में भयंकर गर्म हवाएं चल रही हैं। ओडिशा 108 दिनों के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर रहा।

मृदा विज्ञान मत्रालय की भारत में जलवायु परिवर्तन की समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में समाप्त 30 वर्ष की अवधि के दौरान सर्वाधिक गर्म दिन में दर्ज तापमान 0.63 प्रतिशत बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह सर्वाधिक गर्म दिन के दौरान तापमान में बढ़ोतारी इस शताब्दी के अंत तक 4.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है।



प्रभावित हो सकते हैं इसमें नक्सान 22

प्रतिशत हाल सकता है, इसने नुकसान 2.2 प्रतिशत तक सीमित रह सकता है। चांदी और अमेरिका में व्यष्टि गर्मी से काम के घंटों में नुकसान 1 प्रतिशत से कम रह सकता है। आईएलओन रिपोर्ट, 2019 में कहा गया है कि गर्म मौसम से कृषि क्षेत्र पर सर्वाधिक असर देता है, जिसमें भारत में भी साथे भारत में सप्तलब है कि देश के ज्यादातर राज्य अक्सर अत्यधिक गर्मी में झूलास होते हैं। पिछले 12 साल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अत्यधिक गर्मी वाले दिनों की संख्या (145) सबसे अधिक रही। आंध्र प्रदेश में इसतरह के दिनों की संख्या 111 रही और उत्तर प्रदेश में

**अब कोई भी शख्स घर पर नहीं पाल सकेगा।
सारस, योगी सरकार का फैसला**

- सीएम की अध्यक्षता में राज्य वन्य

-यूपी में आरिफ पर सारस पालने वे
मामले में केस दर्ज

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की 14वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश की जैव विविधता को संरक्षित करने और इको पर्यटन की संभावनाओं को विस्तारित करने सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमंत्री ने दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में ही फैसला लिया गया कि अब कोई राज्य पक्षी 'सारस' को घर पर नहीं पाल पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारस के संरक्षण के लिए वार्षिक 100 करोड़ रुपये का बजेट दिया।

के सरकारी कानूनों के लिए कावयोजना बनाने का लिए नियमित दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में यूपी में आरिफ नामक के शख्स द्वारा सारस पालने का मामला कार्फाय सुरक्षियों में रहा था। आरिफ को अगस्त 2022 में घायल अवस्था में एक सारस मिला था। आरिफ ने उसका इलाज किया, तब से सारस उसके साथ रहना लग गया और वो जहां भी जाता सारस उसके साथ ही जाता था। यह मामला तब ज्यादा चर्चा में आया था। जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों के किसी

सुनकर आरिफ से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद

कारण काम करने का संबंध में ऐसी खबरें आयी हैं कि देश के ज्यादातर राजनीतिक गर्मी में झूलस रहे हैं। पिछले दो वर्षों में अनुच्छेद 111 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग की संख्या बढ़ रही है। अब तक इस संबंध में ऐसी खबरें आयी हैं कि देश के घटों में अनुच्छेद 111 का उपलब्ध अंकड़ा के अनुसार लाइसेंसिंग की संख्या बढ़ रही है। अब तक इस संबंध में ऐसी खबरें आयी हैं कि देश के घटों में अनुच्छेद 111 का उपलब्ध अंकड़ा के अनुसार लाइसेंसिंग की संख्या बढ़ रही है।

प्रशासन ने अरिफ को नोटिस जारी किया था औ वन विभाग अरिफ के सारस को अपने साथ ले था। इस मामले में बन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रवधानों के उल्लंघन के आरोप में आयोजित खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है।

राज्य बन्य जीव बोर्ड की बैठक में सीएम यंग अदिल्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के राज्य 'बारहसिंघा' और राज्य पक्षी 'सारस' के संरक्षण लिए नियोजित प्रयास करने होंगे। इस संबंध कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने बैठक में कहा कि यह सुखद है कि नमामि परियोजना के माध्यम से अविवर और निर्मल हो गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोत्तर हुई है।

रने के घंटों में 3 रें आने का य अक्सर न 12 साल जस्थान में (145) अस्तरह के से पार में

विभाग, नगर विकास, पीडब्ल्यूडी और आवास विभाग मिलकर अच्छी कार्ययोजना तैयार करें। ८ अप्रैल २०१४ में कुल ११७ बाघ प्रदेश में थे, जो २०१८ बढ़कर १७३ हो गए हैं। विगत दिनों जारी सिपोर्ट शिवालिक एंड गंगा प्लेन लैंडस्केप में ८०४ बाघों होने की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुखद संकेत है। बीते २ वर्षों में २८ तेंदुआ, ५ तेंदुबाल और ६ बाघों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। बन्य जीवों के रेस्क्यू में संवेदनशीलता के समानकों का प्रमाण ध्यान मता जाए।

बैठक में बताया गया कि वेटलैंड संरक्षण अंग पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण अब तक प्रदेश में 10 रामसर साइट घोषित किए गए हैं। इनमें आगंता रिवर, बुलन्दशहर, सरसर्झ नावर झील, डियावा नवाबगंज पक्षी विहार, ऊवा, सांडी पक्षी विहार, हरदोई, समसपुर पक्षी विहार, रायबेरेल, पार्किंटोअरगा पक्षी विहार, गोंडा, समान पक्षी विहार मैनपुरी, सूरसरोवर पक्षी विहार, आगरा, बखिरा पक्षी विहार, संतकबीरनगर तथा हैदरपुर वेटलैंड सुजपक्फरनगर शामिल हैं। वेटलैंड संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए। यहां पर्यटन सुविधाओं वाला विकास किया जाए। जनपद संतकबीर नगर व बखिरा झील इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं से समर्पित हुए हैं। यहां के विकास के लिए बेहतर कार्ययोजना तैयार करें।



भ्रष्टाचार प्रतियोगिता में

&

भ्रष्टाचार की जानकारी देने

**National Rights Group
Youtube Channel**

krantisamay@gmail.com

9879141480

fight against corruption india

**भारत में भ्रष्टाचार
के खिलाफ लड़ाई**